



विवादों के बीच लोकपाल का कदम पीछे, लगजरी BMW खरीद का फैसला बदला, टेंडर रद्द कर बचाई साख

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए गठित देश की सर्वोच्च संस्था लोकपाल आखिरकार अपने ही एक फैसले को लेकर पीछे हटती नजर आई है। सात लगजरी BMW कारों की खरीद को लेकर उठे तीखे राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बाद लोकपाल ने इस विवादित टेंडर को रद्द कर दिया है। सार्वजनिक धन के इस्तेमाल और संस्था की नैतिक जिम्मेदारी को लेकर जिस तरह सवाल उठे, उसके बाद यह फैसला लोकपाल के लिए एक तरह का ‘लगजरी यू-टर्न’ माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, लोकपाल की पूर्ण पीठ ने इस मुद्दे पर मंथन के बाद 16 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक संशोधन जारी कर टेंडर को निरस्त करने का निर्णय लिया। यह पूरा विवाद 16 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था,

जब लोकपाल ने सात BMW 3 Series 330Li कारों की आपूर्ति के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया। प्रस्ताव के अनुसार, ये सभी लगजरी कारें लोकपाल के अध्यक्ष और उसके छह सदस्यों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी जानी थीं। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी तक में सवाल उठने लगे कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्था को आखिर इतनी महंगी और लगजरी गाड़ियों की जरूरत क्यों पड़ी। आलोचकों का कहना था कि यह कदम लोकपाल की मूल भावना और उसकी सादगीपूर्ण, निष्पक्ष छवि के बिल्कुल विपरीत है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को हाथोंहाथ लिया और केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम



रमेश ने सोशल मीडिया पर तीखा तंज कसते हुए लोकपाल को “शोकपाल” तक कह दिया, जिससे यह विवाद और गहरा गया। वहीं, पूर्व नौकरशाह अमिताभ कांत ने भी

सार्वजनिक मंच से अपील की कि लोकपाल को यह टेंडर रद्द करना चाहिए और अगर वाहन खरीदने ही हैं तो भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विचार किया जाना

चाहिए। सिविल सोसाइटी के कई संगठनों और बुद्धिजीवियों ने भी कहा कि जब आम जनता महंगाई और संसाधनों की कमी से जूझ रही है, तब एक संवैधानिक संस्था

द्वारा करोड़ों रुपये की लगजरी कारों की योजना नैतिक रूप से गलत संदेश देती है। टेंडर दस्तावेजों में जिन कारों की मांग की गई थी, वे BMW 330Li M Sport मॉडल थीं, जिनका रंग सफेद और व्हीलबेस लंबा होना तय किया गया था। नई दिल्ली में इन सात कारों की अनुमानित ऑन-रोड कीमत करीब पांच करोड़ रुपये आंकी गई थी। इनका उपयोग लोकपाल के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ए. एम. खानविलकर, और संस्था के छह अन्य सदस्यों के लिए प्रस्तावित था। कानून के तहत लोकपाल में अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, ऐसे में यह साफ था कि यह खरीद शीर्ष पदाधिकारियों की सुविधा के लिए ही की जा रही थी। विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। टेंडर की शर्तों में यह भी उल्लेख

था कि चयनित वेंडर को सिर्फ कारों उपलब्ध नहीं करानी होगी, बल्कि ड्राइवरों और नामित कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी होगी। इसमें BMW कारों के कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी फीचर्स, इमरजेंसी हैंडलिंग, पार्किंग तकनीक और फ्यूल एफिशिएंसी मोड्स तक की ट्रेनिंग शामिल थी। इन शर्तों ने भी आलोचकों को यह कहने का मौका दिया कि यह पूरी योजना जरूरत से ज्यादा शाही और गैर-जरूरी है। लगातार बढ़ते दबाव और आलोचना के बीच लोकपाल का यह फैसला सामने आया कि टेंडर को ही रद्द कर दिया जाए। हालांकि, संस्था की ओर से इस निर्णय के पीछे कोई विस्तृत आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शीर्ष स्तर पर हुई बैठकों में यह महसूस किया गया

कि इस मुद्दे से लोकपाल की साख को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में विवाद को और बढ़ने देने के बजाय पीछे हटना ही बेहतर विकल्प समझा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह फैसला लोकपाल द्वारा अपनी विश्वसनीयता बचाने और जनता के बीच संयम, पारदर्शिता और नैतिकता की छवि बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाली संस्था अगर खुद ही विलासिता के आरोपों में घिर जाए, तो उसकी नैतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में BMW टेंडर रद्द करना लोकपाल के लिए एक जरूरी सुधारात्मक कदम माना जा रहा है, जो यह संदेश देता है कि सार्वजनिक आलोचना और जनभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

तनातनी के बीच भरोसे की परंपरा कायम, भारत पाकिस्तान ने फिर साझा की परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में लंबे समय से चली आ रही तल्खी, सीमा पर तनाव और कूटनीतिक मतभेदों के बावजूद एक अहम भरोसेमंद परंपरा एक बार फिर निभाई गई है। दोनों देशों ने गुरुवार को अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे के साथ साझा की। यह प्रक्रिया तीन दशक पुरानी उस द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत पूरी की गई, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के परमाणु ठिकानों को किसी भी तरह के हमले से सुरक्षित रखना और अनजाने टकराव की आशंका को कम करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह आदान-प्रदान पूरी तरह से राजनयिक माध्यमों के जरिए किया गया। नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने तय प्रोटोकॉल के अनुसार एक-दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी सौंपी। मौजूदा समय में जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद लगभग ठप है और सीमा पर तनाव की खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं, ऐसे में इस प्रक्रिया का पूरा होना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खास



महत्व रखता है। दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच “परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध” से संबंधित समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत दोनों देशों पर यह बाध्यता है कि वे हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपें। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में एक-दूसरे के परमाणु ढांचों को निशाना न बनाया जाए, चाहे हालात कितने ही तनावपूर्ण क्यों न हों। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सूचियों का लगातार 35वां आदान-प्रदान है।

पहली बार यह प्रक्रिया 1 जनवरी 1992 को पूरी की गई थी और तब से हर साल बिना किसी रुकावट के इसे निभाया जाता रहा है। यह तथ्य अपने-आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान भारत-पाकिस्तान संबंध कई उतार-चढ़ाव से गुजरे हैं, जिनमें युद्ध जैसे हालात, कारगिल संघर्ष, संसद और मुंबई हमले, पुलवामा और 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 27 जनवरी 1991 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत दोनों देशों पर यह बाध्यता है कि वे हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपें। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में एक-दूसरे के परमाणु ढांचों को निशाना न बनाया जाए, चाहे हालात कितने ही तनावपूर्ण क्यों न हों। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सूचियों का लगातार 35वां आदान-प्रदान है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी यह संदेश देती है कि दोनों देश परमाणु सुरक्षा के मसले पर जिम्मेदार रवैया अपनाने हैं। हालांकि भारत की ओर से यह भी दोहराया गया है कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथ पर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी द्विपक्षीय रिश्तों में वास्तविक सुधार संभव है। इसके बावजूद परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा करने जैसी व्यवस्थाओं को नई दिल्ली रणनीतिक और मानवीय दृष्टि से जरूरी मानती है, क्योंकि किसी भी तरह की चूक या गलत आकलन के परिणाम पूरे क्षेत्र के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। कुल मिलाकर, भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का यह वार्षिक आदान-प्रदान उस न्यूनतम संवाद और भरोसे की कड़ी को दर्शाता है, जो तमाम मतभेदों और तनावों के बावजूद अब तक कायम है। यह परंपरा इस बात की याद दिलाती है कि टकराव के दौर में भी कुछ ऐसे समझौते होते हैं, जो शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य माने जाते हैं और जिन्हें निभाना दोनों देशों के हित में है।

(जीएनएस)। शरियतपुर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। एक बार फिर ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी चिंता में डाल दिया है। शरियतपुर जिले में 50 वर्षीय हिंदू दवा विक्रेता खोकन दास पर सरेहा हिसक हमला किया गया, जिसमें उन्हें बेरहमी से पीटा गया और बाद में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाते की कोशिश की गई। यह घटना 31 दिसंबर की बताई जा रही है, जब खोकन दास रोज की तरह अपना काम खस कर घर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने पहले खोकन दास पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद भीड़ ने उन्हें लात-मुंसों से पीटना शुरू कर दिया। जब इतना भी काफी नहीं लगा, तो आरोप है कि उनके शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की गई। अस्पतास में निशाना बनाया था। उस मामले में दीपू चंद्र दास को पीड़ित लोगो की दखल और अफय-तफरी के कारण वे पूरी तरह जिंदा नहीं जल पाए, लेकिन इस हमले में वे बुरी तरह झुलस गए। उन्हे गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में



भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। यह घटना कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी का एक और भयावह उदाहरण है। इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में हिंदू गार्मेट वेंकर दीपू चंद्र दास को भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में निशाना बनाया था। उस मामले में दीपू चंद्र दास को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर पेड़ से लटकया गया और अंत में उनके शरीर पर आग लगा दी गई, जिससे उनकी मौत के लिए आग लगा दी गई, जिससे उनकी मौत के लिए आग लगा दी गई, जिससे उनकी मौत के लिए आग लगा दी गई। बाद में हुई जांच में ईशनिंदा के आरोप निराधार पाए गए, और पुलिस ने कई

निशाना बनाकर आगजनी की घटनाएं सामने आईं। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ मामलों में परिवारों को घर के अंदर बंद कर जलाने की कोशिश की गई, हालांकि समय रहते लोग जान बचाने में सफल रहे। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों में डर फैलाने का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषकों का कहना है कि मुहम्मद यूनस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। हालांकि सरकार की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दावे किए जा

रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होती, जिससे अपराधियों के हाौसले और बुलंद हो जाते हैं। इन घटनाओं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पिछले सप्ताह भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता जताई थी और स्पष्ट कहा था कि वह अपने पड़ोसी देश में हो रहे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। इसके अलावा कई वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने भी बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शरियतपुर की ताजा घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय कब तक इस तरह के हमलों का शिकार बनते रहेंगे। खोकन दास जैसे आम नागरिक, जो केवल अपनी रोजी-रोटी कमाने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन्हें भी इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़े, तो यह पूरे समाज और शासन व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी है।

असम में चुनावी साल से पहले भाजपा का बड़ा सियासी दांव, 37 लाख महिलाओं को एकमुश्त 8 हजार रुपये का ऐलान

(जीएनएस)। दिसपुर। आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच असम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार मॉडल को तर्ज पर असम में भी महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़ा चुनावी दांव चला है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य की 37 लाख महिलाओं को एकमुश्त 8 हजार रुपये की नकद सहायता दी जाएगी। यह रकम राज्य सरकार की महत्वकांक्षी ओरुनोदेई योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं को दी जाएगी, जिससे चुनाव से पहले सरकार ने एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह सहायता राशि बोहाग बिहू से पहले महिलाओं के खातों में पहुंचा दी जाएगी। सरकार के मुताबिक 20 फरवरी को यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रान्सफर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं की आर्थिक मजबूती और पारिवारिक जरूरतों को सहारा देने की दिशा में अहम कदम बताया है। सरकारी जानकारी के अनुसार, पोषित 8 हजार रुपये की राशि में ओरुनोदेई योजना के तहत जनवरी से अप्रैल तक मिलने वाले 5 हजार रुपये पहले से शामिल हैं। इसके अलावा 3 हजार रुपये अतिरिक्त राशि बोहाग बिहू के उपहार के रूप में दी जाएगी। इस तरह सरकार ने एक साथ चार महाने की सहायता और त्योहार की सीगात देकर महिलाओं को राहत देने का प्रयास किया है। बोहाग बिहू से पहले मिलने वाली यह राशि न सिर्फ आर्थिक राहत बनेगी, महिलाओं को हरे महाने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे असम सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में गिना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि यह फैसला सिर्फ कल्याणकारी योजना भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे साफ तौर पर चुनावी

रणनीति भी दिखाई देती है। बिहार में महिलाओं को नकद सहायता और सामाजिक योजनाओं के जरिए जिस तरह से राजनीतिक लाभ मिला था, उसी मॉडल को अब असम में लागू करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से कुछ महीने पहले एकमुश्त बड़ी राशि देना महादत्ताओं, खासकर महिला वोटर्स के बीच सरकार की पकड़ मजबूत कर सकता है। सरकार का दावा है कि इस पहल का मकसद महंगाई के दौर में महिलाओं और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देना है, ताकि वे दैनिक जरूरतों और त्योहार से जुड़े खर्च आसानी से पूरा कर सकें। असम जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी ग्रामीण और निम्न आय वर्ग से जुड़ी है, इस तरह की नकद सहायता योजनाएं सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि ओरुनोदेई योजना को पहले से ही सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया जाता रहा है। वहीं विपक्षी दलों ने इस ऐलान को लेकर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार को महिलाओं और गरीबों की याद आ रही है और सरकारी खजाने का इस्तेमाल वोट बैंक मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष इसे चुनावी ‘लॉलीपॉप’ बता रहा है, जबकि भाजपा और राज्य सरकार इसे जनकल्याण और सामाजिक जिम्मेदारी का कदम बता रही है। फिलहाल इतना तय है कि 37 लाख महिलाओं को एक साथ 8 हजार रुपये देने का फैसला असम की सियासत में बड़ा असर डालने वाला है। बोहाग बिहू से पहले मिलने वाली यह राशि न सिर्फ आर्थिक राहत बनेगी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक मजबूत चुनावी हथियार के तौर पर भी देखी जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह ‘बिहार वाला दांव’ असम में भी भाजपा को वही सियासी बढ़त दिला पाता है या नहीं।

महंगाई की आग में सुलगता ईरान, सड़कों पर उतरा आक्रोश हिंसा में बदला

(जीएनएस)। दुबई। ईरान में गहराते आर्थिक संकट ने अब खुलकर सड़कों पर उग्र रूप ले लिया है। बढ़ती महंगाई, गिरती राष्ट्रीय मुद्रा और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन बुधवार देर रात हिंसक हो गया। पश्चिमी लोरैस्टान प्रांत के कुहदाश्त शहर में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए, जब सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें हुईं। इस हिंसा में अर्धसैनिक बल बसिज मिलिशिया के एक सदस्य की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य सुरक्षाकर्मियों घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव और भय का माहौल है। यह विरोध प्रदर्शन शुरूआत में अपेक्षाकृत शांत था और रविवार को दुकानदारों ने अपने कारोबार पर पड़ रहे आर्थिक दबाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन देखते ही देखते यह आंदोलन स्थानीय दायरे से बाहर निकलकर देशव्यापी आक्रोश में तब्दील हो गया। महंगाई की मार झेल रहे आम नागरिक, छात्र और व्यापारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। कई शहरों में बाजार बंद रहे और जनजीवन आंशिक रूप से ठप पड़ गया। लोगों का कहना है कि उनकी आमदनी लगातार घट रही है, जबकि खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, बुधवार रात कई शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव हुआ। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने ऑप् गैस के गोले छोड़े और कुछ जगहों पर गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आईं। कई इलाकों में सरकारि इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। कुहदाश्त में हुई हिंसक झड़पों के बाद वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने राजनीतिक नारों के साथ-साथ ईरान के निर्वासित राजा रजा पहलवी के

समर्थन में भी नारे लगाए। यह बात ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए खास तौर पर संवेदनशील मानी जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में कई को रिहा कर दिया गया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन प्रदर्शनों के पीछे असाामाजिक और देशविरोधी तत्वों का हाथ होने का आरोप लगाया है और कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। आर्थिक आंकड़े भी हालात की गंभीरता को उजागर करते हैं। ईरान में दिसंबर महीने में मुद्रास्फीति दर 42.5 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिसने आम लोगों की कम्मर तोड़ दी है। राष्ट्रीय मुद्रा रियाल की लगातार गिरती कीमत ने हालात और बदतर बना दिए हैं। विश्वविद्यालयों के छात्र, छोटे व्यापारी और नौकरपेशा वर्ग सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का बोझ सीधे जनता पर पड़ रहा है। सरकार की ओर से हालात संपालने की कोशिशों भी सामने आई हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने संकेत दिए हैं कि सरकार प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को सुनने के लिए तैयार है और संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। वहीं, सरकारी प्रवक्ता फातिमा मोहजरानी ने कहा है कि अधिकारी टैंड यूनिटों, व्यापारिक संगठनों और दुकानदारों के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत कर रहे हैं, ताकि स्थिति को शांत किया जा सके। फिलहाल ईरान के कई हिस्सों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सड़कों पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और सरकार किसी भी तरह की अराजकता को रोकने के लिए सतर्क है। लेकिन जिस तरह से आर्थिक दबाव और जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उससे यह साफ है कि ईरान के सामने यह संकट सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि भरोसे और आजीविका से जुड़ा एक गहरा सामाजिक और आर्थिक सवाल बन चुका है।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber

Jio tv+

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba TV

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विकास, विश्वास और विजन के साथ नव वर्ष की विकास भरी शुरुआत : वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास

► **वीरमगाम, देत्रोज और मांडल तहसीलों को 497 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात**

► **कभी संसाधनों की कमी, वर्षा आधारित खेती और रोजगार के लिए युवाओं के पलायन जैसी विकट स्थिति से जुझता मांडल, बेचराजी और वीरमगाम क्षेत्र आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास विजन से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) और ऑटो हब बन गया है।**

इस संदर्भ में श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने अंतिम व्यक्ति के हित के संकल्प और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र से विकास की चरम सीमा का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति

(जीएनएस)। : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वर्ष 2026 के पहले दिन गुरुवार को वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और ओवरब्रिज सहित 497 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कभी संसाधनों की कमी, वर्षा आधारित खेती और रोजगार के लिए युवाओं के पलायन जैसी विकट स्थिति से जुझता मांडल, बेचराजी और वीरमगाम क्षेत्र आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकास विजन से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) और ऑटो हब बन गया है। इस संदर्भ में श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने अंतिम व्यक्ति के हित के संकल्प और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र से विकास की चरम सीमा का उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि विकास की राजनीति

का जो दृष्टिकोण प्रधानमंत्री ने अपनाया है, उसे अब सभी ने स्वीकार कर लिया है और बिहार के हाल ही में हुए चुनाव के परिणाम इसका आदर्श उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में पिछले ढाई दशक से अधिक समय से श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी सहित जो विकास कार्य डबल इंजन सरकार की गति से हुए हैं, उससे गुजरात देश के विकास का प्रोथ इंजन बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए वीरमगाम-मांडल क्षेत्र में रोड और रेलवे सहित अनेक कार्य हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में ही मांडल-बेचराजी एसआईआर को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों के 488 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हुए हैं। एसआईआर से जुड़ने वाले हाईवे, परिवहन में बुनियादी ढांचे के विकास और फोरलेन रोड तथा रेलवे ओवरब्रिज के कारण इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा और नई गति



मिलेगी। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होने से कोकता फाटक पर वर्षों से चली आ रही ट्रैफिक की समस्या खत्म होगी, जिससे लगभग 1 लाख नागरिकों के समय और ईंधन की बचत होगी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी

परियोजनाओं की गति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विभिन्न एक्सप्रेस-वे, कॉरिडोर और रणनीतिक पुलों एवं सुरंगों के कार्य पूरे किए गए हैं। जहां 2014

से पहले योजना 12 किमी नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता था, वहीं आज योजना 34 किमी नेशनल हाईवे बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने भी नमो शक्ति एक्सप्रेस-वे और 1155 किमी के 12 गरवी गुजरात हाईस्पीड कॉरिडोर के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नागरिकों से अपील की कि जब इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हो रहा हो, तब हमें भी स्वच्छता पर विशेष जोर देना चाहिए और स्वच्छता लोगों का सहज स्वभाव बनना चाहिए। इस अवसर पर वीरमगाम के विधायक श्री हार्दिक पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, जिनका लाभ स्थानीय क्षेत्र सहित शंखेश्वर और बेचराजी के श्रद्धालुओं को मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले तीन वर्षों में वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए से अधिक विकास के कार्य मिले हैं।

विधायक श्री पटेल ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा इस बात की चिंता की गई है कि विकास से कोई भी वंचित न रह जाए। इस मौके पर सुपोषित गुजरात अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेट बास्केट वितरित किए। सड़क एवं भवन विभाग के मुख्य अभियंता ने स्वागत भाषण दिया। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वीरमगाम विधानसभा क्षेत्र की जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें वीरमगाम नगर पालिका से मांडल-दसाड़ा रोड का 285 करोड़ रुपए का कार्य, वीरमगाम शहर के रैयापुर ओवरब्रिज का 91 करोड़ रुपए का कार्य, मांडल तहसील के विठुलापुर से देत्रोज-कड़ी रोड के रिसर्फेसिंग का 55 करोड़ रुपए का कार्य, वीरमगाम तहसील के थोरी मुबारक से लीया-वांसवा रोड का 39 करोड़ रुपए का

कार्य, करकथल-हांसलपुर रोड का 12 करोड़ रुपए का कार्य, देत्रोज नए सर्किट हाउस का 5 करोड़ रुपए का कार्य, वीरमगाम नए सर्किट हाउस का 5 करोड़ रुपए कार्य, देत्रोज सब रजिस्ट्रार कार्यालय का 2.45 करोड़ रुपए का कार्य तथा वीरमगाम तहसील के सचाणा बाइपास रोड के 3 करोड़ रुपए के कार्य सहित विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कंचना वाघेला, जिला कलेक्टर श्री सुजीत कुमार, जिला विकास अधिकारी श्री विदेह खरे, जिला पुलिस अधीक्षक श्री ओम प्रकाश जी, अग्रणी श्री शैरेशभाई दावड़ा, सड़क एवं भवन विभाग के मुख्य अभियंता एवं विशेष सचिव श्री जे.ए. गांधी, तहसील पंचायतों के अध्यक्ष, वीरमगाम नगर पालिका अध्यक्ष, पालिका एवं तहसील पंचायत के सदस्य, पूर्व विधायक और सामाजिक कार्य राजनीतिक अग्रणियों सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग अहमदाबाद में खेमराज मीना ने जनसंपर्क अधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग, अहमदाबाद में दिनांक 01 जनवरी 2026 को श्री खेमराज मीना ने जनसंपर्क अधिकारी (PRO) के पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रमभार ग्रहण करने से पूर्व खेमराज मीना पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंटीर में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इससे पूर्व मीना पश्चिम रेलवे के वडोदरा

मंडल तथा दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल में भी जनसंपर्क अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता के रूप में खेमराज मीना ने भारतीय जन संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उनके अनुभव एवं कार्यकुशलता से पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग के जनसंपर्क कार्यों को नई दिशा मिलेगी।

पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट होंगी

महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेडेशन हेतु कुछ ट्रेनों के लिए अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा बोरीवली-कांदिवली के बीच 5वीं एवं 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य से संबंधित आवश्यक नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य को सुचारु रूप से संपन्न करने हेतु कुछ मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के अस्थायी नियमन की योजना बनाई गई है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दो मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें - ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार-बोरीवली एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद-बोरीवली एक्सप्रेस को 17 जनवरी, 2026 तक वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इसी प्रकार, दो मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें - ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली-नंदुरबार

एक्सप्रेस तथा ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-अहमदाबाद एक्सप्रेस को 18 जनवरी, 2026 तक वसई रोड स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन अधीक्षकों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें तथा उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

भारतीय रेल का राष्ट्र को नव वर्ष का उपहार: गुवाहाटी और हावड़ा के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

(जीएनएस)। रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली के रेल भवन में आयोजित बैठक में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए घोषणा की कि असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संचालन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का संपूर्ण परीक्षण, जांच और प्रमाणिकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जनवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस मार्ग पर पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय रेल, राष्ट्र और इसके लिए यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि 2026 में कई यात्री-केंद्रित पहल शुरू की जाएंगी और यह भारतीय रेल के लिए बड़े सुधारों वाला वर्ष होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से असम राज्य के कामरूप महानगरपालिका और बोंगाई गांव और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार,

जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पूर्वी बर्धमान, हुगली और हावड़ा जैसे जिलों को लाभ मिलेगा। ट्रेन में 16 कोच होंगे, इनमें 11 श्री-टियर एसी कोच, 4 टू-टियर एसी कोच और 1 फर्स्ट-क्लास एसी कोच शामिल हैं। इसकी कुल क्षमता लगभग 823 यात्रियों की होगी। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूरी तरह से नए सस्पेंशन वाली एक नई बोगी विकसित की गई है। डिजाइन के मानकों को नए स्तर पर ले जाया गया है। इसके आंतरिक भाग और सिडिंयां एरॉनॉमिक डिजाइन पर आधारित हैं, और सुरक्षा के लिए विशेष माफदंड लागू किए गए हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रात्रिकालीन यात्राओं के लिए आरामदायक, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता का अनुभव प्रदान करेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की समय सारिणी इस प्रकार बनाई गई है कि यह शाम को अपने प्रस्थान स्थल से रवाना होकर अगली सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रियों को क्षेत्र विशेष व्यंजनों का आनंद मिलेगा।

गुवाहाटी से शुरू होने वाली ट्रेन में प्रमाणिक असमिया व्यंजन परोसे जाएंगे, जबकि कोलकाता से शुरू होने वाली ट्रेन में पारंपरिक बंगाली व्यंजन परोसे जाएंगे। इससे रेल में आनंददायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भोजन मिलना सुनिश्चित होगा। **वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की विशेषताएं:** ► 180 किमी प्रति घंटे तक की गति वाली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन ► बेहतर तकिए के साथ एरॉनॉमिक (एसे) उत्पाद, जो आरामदायक, सुरक्षित और सुरक्षित हों) रूप से डिजाइन किए गए बर्थ ► सुगम आवागमन के लिए प्रवेश द्वारों सहित स्वचालित दरवाजे ► बेहतर सस्पेंशन और शोर कम करने की क्षमता के साथ बेहतर यात्रा का आनंद लें। **कवच से सुसज्जित** ► उच्च स्वच्छता बनाए रखने के लिए कोटागुनाका तकनीक ► उन्नत निर्यंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों

से सुसज्जित ड्राइवर केबिन ► वायुगतिकीय बाहरी बनावट और स्वचालित बाहरी यात्री दरवाजे **दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था** ► आपातकालीन स्थिति में यात्री और ट्रेन प्रबंधक/लोकों को पायलट के बीच संचार के लिए आपातकालीन टॉक-बैक यूनिट। ► सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ► विद्युत कैबिनेट और शौचालयों में एरोसोल आधारित अग्नि पहचान और शमन प्रणाली से अग्नि सुरक्षा में सुधार हुआ है। ► पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारतीय रेल के एक नए युग की शुरुआत है। यह रात भर की यात्रा के लिए गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं का संगम है। यह भारतीय रेल की यात्री-केंद्रित सेवाओं, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यात्रियों को एक सुरक्षित, तेज, सुविधाजनक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यात्रा प्रदान करती है।

पीएनजी ज्वेलर्स ने लाइटस्टाइल बाय पीएनजी के साथ विकास के अगले पड़ाव को गति दी, सारा तेंदुलकर को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया

(जीएनएस)। पुणे: पीएनजी ज्वेलर्स के समकालीन हल्के वजन वाले उत्तम आभूषण ब्रांड लाइटस्टाइल बाय पीएनजी ने सारा तेंदुलकर को अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है, यह कदम भारत के भविष्य के ज्वेलरी उपभोक्ताओं से ब्रांड के जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह साझेदारी पीएनजी ज्वेलर्स के पुराने ग्राहकों और भविष्य के ग्राहकों के बीच एक धोरणात्मक सेतु के रूप में लाइटस्टाइल की भूमिका को और मजबूत करती है। पीएनजी ज्वेलर्स लगभग दो सदियों से पीढ़ियों से एक विश्वसनीय नाम रहा है, वहीं लाइटस्टाइल को विशेष रूप से आधुनिक रिटेल प्रारूप, समकालीन डिजाइन भाषा और एक सर्वव्यापी अनुभव के माध्यम से अगली पीढ़ी के लिए प्रारंभिक बने रहने के लिए सोच-समझकर तैयार किया गया है। लाइटस्टाइल के पीछे की व्यापक सोच के बारे में बात करते हुए, पीएनजी ज्वेलर्स के अध्यक्ष और व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. सोरभ गाडगीळ ने कहा, “लाइटस्टाइल बाय पीएनजी हमारे मौजूदा ग्राहकों और भविष्य के ग्राहकों के जोड़ने का एक अच्छा और दीर्घकालिक प्रयास है। पीएनजी ने पीढ़ियों से विश्वास संपादन किया है, लेकिन हमारे लिए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम आज के युवा उपभोक्तोंओं की सोच, खरीदारी और अभिव्यक्ति के तरीके के अनुरूप बने रहें। लाइटस्टाइल को एक आधुनिक रिटेल फॉर्मेट में बन बनाया गया है, जिसमें मजबूत ओमनीचैनल उपस्थिति है और इसे केवल पारंपरिक अवसरों तक सीमित न रखकर रोज के पलों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया



गया है। यह कोई शॉर्ट टर्म स्ट्राइल पहल नहीं है, बल्कि पीएनजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र है, जिसमें मचेंड्राईजिंग, प्लानिंग, मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे पायलट स्टोर्स को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने हमें प्रमुख बाजारों में ब्रांड को संचरित तरीके से विस्तार करने का आत्मविश्वास दिया है।” सारा तेंदुलकर की स्वाभाविक शालीनता, आधुनिक दृष्टिकोण और मजबूत डिजिटल जुड़ाव उन्हें ब्रांड की विचारधारा के लिए एकदम उपयुक्त

बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर 8.9 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ, उन्हें उनकी आकर्षक स्ट्राइल, प्रामाणिकता और संतुलित व्यक्तित्व के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। उत्कृष्ट डिजाइन, सादगीपूर्ण और आराम को प्राथमिकता देने वाले फैशन के प्रति उनकी पसंद, प्रमुख बाजारों में ब्रांड को संचरित करती हैं, जिनके लिए लाइटस्टाइल बनाया गया है - आत्मविश्वास से तैदुलकर ने कहा, “लाइटस्टाइल सहजता और व्यक्तित्व की भावना को दर्शाता है, जो मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है। इसकी ज्वेलरी हल्की, सोच-समझकर

डिजाइन की गई है और रोज की जिंदगी के लिए उपयुक्त है, जिससे यह साझेदारी मेरे लिए वास्तव में रोमांचक बन जाती है।” इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, लाइटस्टाइल बाय पीएनजी के मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्रमुख हेमंत चट्टाण ने कहा, “सारा उन लाइटस्टाइल के डिजाइन सिद्धांतों के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं। इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए सारा तेंदुलकर ने कहा, “लाइटस्टाइल सहजता और व्यक्तित्व की भावना को दर्शाता है, जो मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है। इसकी ज्वेलरी हल्की, सोच-समझकर

है कि वह भविष्य के उन उपभोक्ताओं के लिए पसंदीदा ज्वेलरी डेस्टिनेशन बने जो डिजाइन, सहजता और प्रामाणिकता को महत्व देते हैं।” ब्रांड एंबेसडर के रूप में, सारा तेंदुलकर ब्रांड और कलेक्शन अभियानों में नजर आएंगी, डिजिटल पहलों, मीडिया इंटरव्यू में भाग लेंगी और प्रमुख स्टोर लॉन्च में शामिल होंगी। इसके अलावा वह चुनिंदा कलेक्शन के रूप में रेल स्ट्राइल म्यूज के रूप में भी काम करेगी। दो साल की यह साझेदारी दिसंबर 2025 में शुरू होगी, और सारा के साथ डिजाइन किए गए कलेक्शन मार्च 2026 से लॉन्च किए जाने की योजना है। लाइटस्टाइल बाय पीएनजी एक स्वतंत्र बिजनेस वंटिकल के रूप में काम करता है, जो उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो पारंपरिक या त्योहारों के अलावा भी आभूषण खरीदती हैं, चाहे वह स्वयं के लिए हो, गिफ्टिंग हो या रोज के पलों के लिए, यह ब्रांड एक सशक्त ओमनीचैनल दृष्टिकोण अपनाता है जो भौतिक स्टोर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट आधारित एंगेजमेंट को एकीकृत करता है। पुणे और गोवा में पायलट स्टोर्स से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद, लाइटस्टाइल अब सुनिश्चित विस्तार के लिए तैयार है। ब्रांड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 50 स्टोर्स तक विस्तार करना है, जिसमें कंपनी के स्वामित्व और फ्रेंचाइजी के दोनों प्रारूप शामिल होंगे, साथ ही एक ऑनलाइन स्टोर और एप भी होगा। विस्तार का प्रारंभिक चरण महाराष्ट्र पर केंद्रित होगा, जिसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में विस्तार किया जाएगा।

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वर्ष 2025 भारतीय ओटोमोबाइल उद्योग के लिए एक नई उम्मीद और मजबूती का साल बनकर उभरा। बीते कुछ वर्षों की सुस्ती और अनिश्चितताओं के बाद इस साल ऑटो बाजार ने जिस तरह रफ्तार पकड़ी, उसने न सिर्फ कंपनियों के चेहरे पर लॉन्च में शामिल होंगे। इसके अलावा भी सरकार का संकेत दिए। जीएसटी में म्यूज के रूप में भी काम करेगी। दो साल की यह साझेदारी दिसंबर 2025 में शुरू होगी, और सारा के साथ डिजाइन किए गए कलेक्शन मार्च 2026 से लॉन्च किए जाने की योजना है। लाइटस्टाइल बाय पीएनजी एक स्वतंत्र बिजनेस वंटिकल के रूप में काम करता है, जो उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो पारंपरिक या त्योहारों के अलावा भी आभूषण खरीदती हैं, चाहे वह स्वयं के लिए हो, गिफ्टिंग हो या रोज के पलों के लिए, यह ब्रांड एक सशक्त ओमनीचैनल दृष्टिकोण अपनाता है जो भौतिक स्टोर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट आधारित एंगेजमेंट को एकीकृत करता है। पुणे और गोवा में पायलट स्टोर्स से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद, लाइटस्टाइल अब सुनिश्चित विस्तार के लिए तैयार है। ब्रांड का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 50 स्टोर्स तक विस्तार करना है, जिसमें कंपनी के स्वामित्व और फ्रेंचाइजी के दोनों प्रारूप शामिल होंगे, साथ ही एक ऑनलाइन स्टोर और एप भी होगा। विस्तार का प्रारंभिक चरण महाराष्ट्र पर केंद्रित होगा, जिसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में विस्तार किया जाएगा।

भी उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। हालांकि, वैश्विक परिस्थितियों और कुछ बाजारों में मांग कमजोर रहने के चलते निर्यात में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन घरेलू बिक्री ने इसकी भरपाई कर दी। किआ इंडिया ने भी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। दिसंबर माह में कंपनी की बिक्री दोगुने से अधिक रही, जिसने साल के अंत में उसकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। पूरे वर्ष की बात करें तो किआ की कुल बिक्री में करीब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कंपनी के एसयूवी और प्रीमियम सेगमेंट के मॉडल्स को ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिससे किआ ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और विपणन को नए स्तर पर बढ़ा दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए भी 2025 उपलब्धियों भरा रहा। कंपनी ने दिसंबर में 25 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 86 हजार से अधिक वाहनों की बिक्री की। घरेलू यात्री वाहन खंड में महिंद्रा की मजबूत मौजूदगी पहले से और सशक्त हुई। खासकर एसयूवी सेगमेंट में कंपनी के नए और अपडेटेड मॉडल्स ने ग्राहकों को आकर्षित किया। ग्रामीण इलाकों में टैक्सी और यूटिलिटी वाहनों की स्थिर मांग ने भी और मांग को नए स्तर पर बढ़ा दिया। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया के लिए 2025 बेहद सफल साबित हुआ। कंपनी ने दिसंबर 2025 में कुल बिक्री में 22 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज करते हुए 2.17 लाख से ज्यादा वाहनों की बिक्री की। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की मजबूत मांग ने इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई। खासकर छोटे और मिड-सेगमेंट की कारों के साथ-साथ यूटिलिटी वाहनों की बिक्री में

स्कোडा ऑटो इंडिया के लिए 2025 ऐतिहासिक साबित हुआ। कंपनी की बिक्री दोगुने से अधिक बढ़कर 72,665 इकाई पर पहुंच गई, जो भारत में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रदर्शन माना जा रहा है। नए मॉडल्स की लॉन्चिंग, बेहतर सर्विस नेटवर्क और आक्रामक मार्केटिंग रणनीति ने स्कोडा को प्रीमियम सेगमेंट में नई पहचान दिलाई। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में भारतीय ओटोमोबाइल उद्योग ने मजबूती और स्थिरता का परिचय दिया। मांग में सुधार, नीतिगत समर्थन और उपभोक्ता विश्वास की वापसी ने सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुझान नए साल में भी जारी रह सकता है। अगर आर्थिक हालात अनुकूल रहें और नीतिगत समर्थन बना रहा, तो 2026 ओटो सेक्टर के लिए और भी बेहतर संभावनाएं लेकर आ सकता है।

पश्चिमी रेलवे निर्माण कार्य

डिजिटल रेलवे मैनेजर (WA), पश्चिमी रेलवे, छठी मंजिल, इंडीयनरेल विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई 400 008. ई-टेंडर नोटिस संख्या: BCT/125-26/292, दिनांक 29.12.2025 आमंत्रित करते हैं। कार्य और स्थान: विहार-जोरावासन संयोजन - 1. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के साथ इनवर्टर सिग्नल उपकरण को बदलने के संबंध में मिलाड में 6। बिस्किंग का निर्माण। 2. वलसाड में G-1 सिग्नल स्टोर बिस्किंग का निर्माण। 3. RPF पोस्ट - B। पर रोड की मरम्मत और नवीनीकरण। (इलेक्ट्रिक (P) कार्यों सहित समग्र टेंडर)। कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 8,14,71,972.89 रुपये। EMD: ₹ 5,57,400/-। प्रया करने की राशि और समय: दि. 23.01.2026 के 15:00 बजे तक। खोलने की तारीख और समय: दि. 23.01.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएं।

हमें लाइक करें: www.facebook.com/WesternRail 0960

